सरकारी निदेशक कार्यरत हैं। फिलहाल 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में 81 रिक्तियां हैं, जिनमें से अधिकांश 1985 में खाली हुई थीं। रिक्तियों की श्रेणी-वार स्थिति इस प्रकार है:-

जमाकर्ता . . .	5
ऋणक . . .	8
कारीगर . . .	11
कार्मिकों की सामान्य श्रेणी .	20
अन्य . .	37

गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्तियां राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजनाएं, 1970 तथा 1980 में दी गयी पद्धति तथा मार्ग-दर्शकों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। उक्त योजना में, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात् इन निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान है।

20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियां भरने के लिए सरकार ने पहले ही आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

खर्च कर दी गई विदेशी प्रतिभूतियां

1332. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फ़ारेन सिक्यूरिटीज इनजास्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस विदेशी प्रतिभूति निधि को भी खर्च कर दिया गया जिसे बहुत असाधारण और विशेष स्थितियों से निपटने के लिए आरक्षित रखा गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस निधि को कब खर्च किया गया; और

(घ) इसके बदले में आयात की गई वस्तुओं का मूल्य और मात्रा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। बहुत असाधारण और विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए कोई विदेशी प्रतिभूति निधि आरक्षित नहीं रखी जाती। विदेशी प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों का एक हिस्सा है। इन प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री आरक्षित प्रबंध के एक हिस्से के रूप में सतत् आधार पर की जाती है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(घ) विदेशी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री संबंधी लेन-देन किसी तरह के निर्यात के बदले में नहीं किया जाता।

Issue of identity cards to voters

1333. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleas-ed to state;

(a) whetheri Government propose to issue identity cards to voters with a view to reducing malpractices during elections; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P• R-KUMARA-MANGALAM): (a) Yes, Sir

(b) Taking into account the huge number of voters expenditure and the administrative steps involved in the operation, the introduction of